

प्रेषक,

एनोएसोनपलच्चाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग
देहरादून : दिनांक : ४ दिसम्बर, 2006
विषय: मै० नीलकण्ठ बैवराजेज प्रा०लि० को पैकेज्ड मिनरल वाटर विनिर्माणक उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम कुलचन्दी में कुल 0.3413 हौ० भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-469/भूमि व्यवस्था-भूमि क्य-2005 दिनांक 03 मार्च, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० नीलकण्ठ बैवराजेज प्रा०लि० को पैकेज्ड मिनरल वाटर विनिर्माणक उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम कुलचन्दी में कुल 0.3413 हौ० भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैँ :-

- 1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— रपॉर्ट जोनिंग क्षेत्र के लिये निर्धारित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 7— क्य की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग, यदि औद्योगिक रो गिन हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से रवीकृत कराने के पश्चात् ही स्थेल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8— स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मल के वेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9— इकाई द्वारा क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग पैकेजड मिनरल वाटर विनिर्माणक उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।
- 10— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रवीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 2— तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(नृप सिंह नपलच्छाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 3— सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— श्री मदन गोपाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मै0 नीलकण्ठ बैवराजेज प्राइली, निवासी— ग्राम लिसौड़ा डाँ0-खतौली, जिला—मुजफ्फरनगर, उ0प्र०।
- 6— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
- 7— गार्ड फाईल।

आहा से,
(सुनील सिंह)
अनु सचिव।